RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 19 AUGUST TO 25 AUGUST 2020 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 05 ■ अंक 52 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

भारत में बैठ कर कीजिए अमेरिकी शेयर बाजार में निवेश Page 2

आईटीआर में नहीं देनी होगी यह अहम जानकारी Page 3

भारत में शुरू होने जा रही है टोयोटा की एसयूवी URan Cruiser की बुकिंग Page 7

editoria!

जरूरी कर सुधार

कर सुधार की ओर भारत ने जो कदम उठाए हैं, वे जरूरी व स्वागतयोग्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में कराधान व्यवस्था को सुधारने के इरादे से जो घोषणाएं की हैं, उनसे टैक्स चुकाने वालों को निश्चित ही खुशी हो रही होगी। इन सुधारों का मुख्य लक्ष्य यदि ईमानदार करदाताओं को बढ़ावा देना है, तो इसकी जरूरत दशकों से महसूस की जा रही थी। अव्वल तो स्वयं प्रधानमंत्री ने बता दिया है कि 130 करोड़ लोगों के देश में केवल डेढ़ करोड़ कर चुकाते हैं। कर चुकाने की क्षमता इससे कहीं ज्यादा लोगों में होगी, लेकिन ज्यादातर लोग कमाई छिपाकर टैक्स चुकाने से बचते रहे हैं। कर वसूली की जो पुरानी या लगभग सामंती व्यवस्था रही है, उसमें कई बार कर चुकाने वाला भी कठघरे में खड़ा कर दिया जाता है। शहर या इलाके के आयकर अधिकारियों में बहुत ताकत होती है और वे अपना 'टारगेट' चुनने के लिए लगभग स्वतंत्र होते हैं। आयकर अधिकारियों की मनमानी और कई बार सरकारों की स्थानीय राजनीति के तहत भी आयकर चुकाने वाले नागरिक निशाने पर आ जाते हैं। अब नए दौर के हिसाब से हो रहे सुधारों से हम बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। सरकार करों के फेसलेस मूल्यांकन अर्थात सीधे संपर्क के बिना ही कर निर्धारण की ओर जो कदम उठा रही है, उसमें व्यावहारिक पहलुओं पर विशेष ध्यान देना होगा। ठीक इसी तरह से कर चुकाने में कोई शिकायत होने पर फेसलेस अपील की सुविधा दी जा रही है, तो जाहिर है, ऑनलाइन सिस्टम को बहुत आसान रखना होगा। इसके साथ ही टैक्स चार्टर का जमीनी लाभ दिखना जरूरी है, ताकि बाकी लोग भी कर देने के लिए प्रेरित हों। प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से आगे बढ़कर ईमानदारी के साथ कर देने का आह्वान किया है, तो इस जरूरत को भी समझा जा सकता है। कोरोना और आर्थिक सुस्ती की वजह से सरकार के राजस्व पर असर पड़ा है। सरकार को यह भी लग रहा है कि बुरे दौर में कर वसूली पिछले वर्षों के मुकाबले घटेगी, यह स्वाभाविक भी है, इसलिए सरकार यह सुधार लेकर आई है। राजस्व बढ़ाने का एक उपाय कर दायरा बढ़ाना होता है, पर आज देश जिस दौर में है, लोगों पर नए टैक्स नहीं लादे जा सकते। अतः वर्तमान करदाताओं को ईमानदारी से और पारदर्शी कर भुगतान की सुविधा देकर सरकार ठीक ही कर रही है। प्रधानमंत्री ने यह भी इशारा किया है कि कर सुधार एक सतत प्रक्रिया है, समय-समय पर सुधार होते रहे हैं, इससे संकेत मिलता है कि अभी अन्य कर सुधार भी संभव हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ईमानदार करदाता की राष्ट्र-निर्माण में बड़ी भूमिका होती है। ईमानदार करदाता के जीवन को आसान बनाने के लिए अमेरिका और कुछ अन्य देशों में बेहतर प्रावधान हैं। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में कर चुकाने वालों की वक्त आने पर मदद करने की परंपरा है, जिसके तहत कोरोना के समय भी कर चुकाने वालों के लिए विशेष राहत, रियायत के प्रबंध किए गए हैं। भारत में भी ऐसे करदाताओं के बारे में सोचना चाहिए, जो वर्षों से कर चुका रहे थे, लेकिन इस बार रोजगार-धंधे के प्रभावित होने से नहीं चुका पा रहे हैं। करदाताओं को कर चुकाने में सुविधा-सम्मान देने के साथ अन्य प्रकार से भी प्रोत्साहित करने पर विचार करना चाहिए। कर मानव सभ्यता की पुरानी परंपरा है, यह जितनी सहज और शालीन हो, उतना अच्छा है।

बड़ा फैसला

RBI ने जारी किए एटीएम आधार के पेमेंट से जुड़े नए नियम

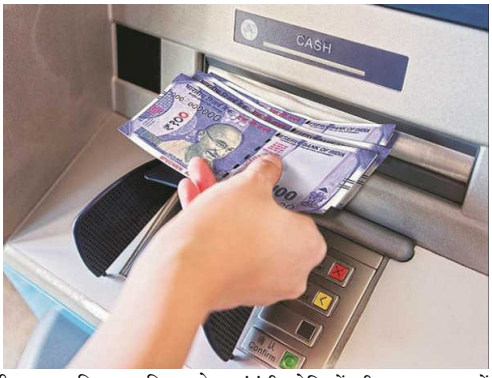

मुंबई।आईपीटी नेटवर्क

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय स्तर पर रिटेल पेमेंट सिस्टम्स के संचालन के लिये अंब्रेला यूनिट स्थापित करने के नियम जारी कर दिए हैं। आरबीआई ने काम शुरू करने की इच्छुक कंपनियों से 26 फरवरी 2021 तक आवेदन मांगे हैं। अंब्रेला यूनिट अपने नाम से रिटेल मार्केट में सिस्टम्स की स्थापना, प्रबंधन और परिचालन कर सकेगी। रिजर्व बैंक की रूपरेखा के मुताबिक, राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार की खुदरा भुगतान प्रणाली का संचालन करने के लिये आवेदन करने वाली कंपनी की नेटवर्थ (Net Worth) 500 करोड़ रुपये से अधिक होनी चाहिए।

एटीएम और आधार आधारित भुगतान की व्यवस्था देखनी होगी- आवेदन करने वाली कंपनी को खुदरा भुगतान के क्षेत्र में एटीएम, खुदरा बिक्री केंद्र और आधार (Aadhaar) आधारित भुगतान सेवाओं समेत पूरा रिटेल सेक्टर की नई भुगतान व्यवस्था का संचालन व व्यवस्था देखनी होगी। कंपनी इस प्रकार के भुगतान केंद्रों की स्थापना करने से लेकर उनकी देखरेख और परिचालन के लिये जवाबदेह होगी। रिजर्व बैंक की ओर से कहा गया है कि ऐसी व्यापक यूनिट्स स्थापित करने वालों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। ये आवेदन 26 फरवरी 2021 को सामान्य कामकाज का समय समाप्त होने से पहले उपलब्ध कराए गए फार्म-ए में भरकर सौंप दिए जाएं।

ये होंगी कंपनी की जिम्मेदारियां, बनाए रखनी होगी ईमानदारी

रिजर्व बैंक ने कहा है कि इस प्रकार की इकाई को बैंकों और गैर-बैंकों के लिये क्लियरिंग व निपटान प्रणाली का परिचालन करने की भी अनुमति होगी। इसमें उसे निपटान, कर्ज, लिक्विडिटी और परिचालन संबंधी जोखिमों की पहचान व उन्हें व्यवस्थित भी करना होगा। साथ ही पूरे सिस्टम की ईमानदारी को बनाए रखना होगा। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि ऐसी कंपनी को खुदरा भुगतान प्रणाली से जुड़े देश के अंदर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाले घटनाक्रमों पर भी नजर रखनी होगी ताकि डॉमेस्टिक सिस्टम पर पड़ने वाले असर, धोखाधड़ी और दूसरी प्रतिक्रियाओं से बचा जा सके। इससे अर्थव्यवस्था पर इन सब के प्रभाव को रोका जा सकेगा।

कंपनियों के आवेदनों की जांच बाहरी सलाहकार समिति करेगी

केंद्रीय बैंक ने कहा है कि आवेदन करने के लिए कंपनी के प्रवर्तक और प्रवर्तक समूह का स्वामित्व व नियंत्रण भारतीय नागरिक के हाथ में होना चाहिए। आवेदन करने वाली इकाई में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है तो उसे विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन कानून (FEMA) के तहत अतिरिक्त पूंजी जरूरत को पूरा करना होगा। इसके लिए सक्षम प्राधिकरण से मंजूरी भी लेनी होगी. रिजर्व बैंक ने कहा है कि आवेदनों जमा कने की अंतिम तिथि के बाद ही प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। आवेदनों की जांच पड़ताल बाहरी सलाहकार समिति करेगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी दी

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को साझा पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिये राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय किया गया। बैठक के बाद सूचना एव प्रसारण मंत्री जावड़ेकर ने संवाददाताओं को बताया "युवाओं को फिलहाल नौकरी के लिये कई अलग अलग परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। ऐसी परीक्षाओं के लिये अभी लगभग 20 भर्ती एजेंसियां हैं और परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थियों को दूसरे स्थानों पर भी जाना पड़ता है।" उन्होंने कहा कि इस संबंध में परेशानियां दूर करने की मांग काफी समय से की जा रही थी । इसे देखते हुए मंत्रिमंडल ने साझा पात्रता परीक्षा लेने के लिये 'राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी' के गठन का निर्णय किया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने इस निर्णय को ऐतिहासिक बताया और कहा कि प्रारंभ में तीन एजेंसियों की परीक्षाएं राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के दायरे में आयेंगी। एक अधिकारी ने बताया कि शुरू में इसके दायरे में रेलवे भर्ती परीक्षा, बैंकों की भर्ती परीक्षा और कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) आयेंगे। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा में हासिल स्कोर तीन साल तक मान्य होंगे। परीक्षा आयोजित करने के लिये हर जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र स्थापित किया जायेगा ।

जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट का निजीकरण!

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट द्वारा लिए गए कई अहम फैसलों के बारे में बताया। इनमें से एक फैसला एयरपोर्ट से जुड़ा है। जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जयपुर, गुवाहटी और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट्स को लीज पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी सरकार ने पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत दी है। यानी ये तीनों एयरपोर्ट अब निजी कंपनियों के हाथों में चले जाएंगे। इस बात के कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे कि मोदी सरकार कुछ एयरपोर्ट्स को निजी हाथों में दे सकती है। प्रकाश जावड़ेकर ने इस अहम फैसले के फायदे भी बताए। उन्होंने कहा कि इससे जो 1070 करोड़ रुपये मिलेंगे, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दूसरे छोटे शहरों में एयरपोर्ट विकसित करने में इस्तेमाल करेगी। ये पैसा काफी काम आएगा। इसका दूसरा फायदा ये होगा कि यात्रियों को अच्छी सुविधा मिलेगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 50 साल के लिए निजी हाथों में दिया है, उसके बाद ये एयरपोर्ट वापस मिल जाएंगे।

सेंसेक्स 86 अंक बढ़त के साथ बंद

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

वैश्विक स्तर पर सकारात्मक रुख के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक की अगुवाई में घरेलू शेयर बाजार में बुधवार को तेजी आयी और बीएसई सेंसेक्स 86 अंक बढ़त के साथ बंद हुआ। तीस शेयरों पर आधारित सेंसेक्स कारोबार के दौरान एक समय 38,788.51 अंक तक चला गया था। लेकिन अंत में यह 86.47 यानी 0.22 प्रतिशत की बढ़त के साथ 38,614.79 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 23.05 अंक यानी 0.20 प्रतिशत की बढ़त के साथ 11,408.40 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के शेयरों में सर्वाधिक लाभ में टेक महिंद्रा रही। इसमें करीब 2 प्रतिशत की तेजी आयी। इसके अलावा भारती एयरटेल, मारुति, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज भी लाभ में रहीं। दूसरी तरफ बजाज ऑटो, ओएनजीसी, नेस्ले इंडिया, एचयूएल और कोटक बैंक में गिरावट रही।

कारोबारियों के अनुसार अमेरिकी शेयर बाजार के कल रिकार्ड उच्च स्तर पर पहुंचने के साथ वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुख रहा, जिसका असर घरेलू बाजार पर पड़ा। इसके अलावा विदेशी पूंजी निवेश जारी रहने से भी निवेशकों की धारणा को बल मिला। एक्सचेंज के पास उपलब्ध आंकड़े के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशकों ने मंगलवार को शुद्ध रूप से 1,134.57 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर खरीदे। एशिया के अन्य बाजारों में जापान में तोक्यो, दक्षिण कोरिया का सोल सकारात्मक दायरे में रहे जबकि चीन के शंघाई और हांगकांग के बाजार में गिरावट दर्ज की गयी। यूरोप के प्रमुख बाजार शुरूआती कारोबार में लाभ में रहे। निवेशकों को संकेत को लेकर अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक के ब्योरे की भी प्रतीक्षा है। उधर, वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड का भाव 0.66 प्रतिशत की गिरावट के साथ 45.16 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। विदेशी विनिमय बाजार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे की गिरावट के साथ 74.82 पर बंद हुआ।

भारत में बैठ कर कीजिए अमेरिकी शेयर बाजार में निवेश

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं और भारत के अलावा दूसरे देश के शेयर बाजार में भी निवेश की चाहत रखते हैं तो यह खबर आपके लिए है। अधिकतर भारतीय निवेशक, अभी तक चाह कर भी अमेरिकी शेयर बाजार में निवेश नहीं कर पाते थे। लेकिन, अब ऐसा संभव हो गया है। इसके लिए एक्सिस बैंक की सहायक कंपनी एक्सिस स्कियोरिटीज ने ग्लोबल इंवेस्टिंग प्लेटफार्म लांच करने की घोषणा की है। अच्छी बात यह है कि भारतीय खुदरा निवेशक शून्य ब्रोकरेज फीस के साथ यूएस स्टॉक्स में असीमित ट्रांजेक्शन कर पाएंगे।

कुछ क्लिक में हो जाएगा यूएस स्टॉक में निवेश

अब निवेशक मात्र कुछ ही क्लिक्स में फेसबुक, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल व अन्य कंपनियों के शेयर्स की खरीद/बिक्री कर सकते हैं; या थीम-आधारित बाजारों या ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं। विशाल वैश्विक बाजार की आसान उपलब्धता के साथ, निवेशक न केवल भौगोलिक डाइवर्सिफिकेशन का लाभ ले सकते हैं बल्कि अपने पोर्टफोलियो को एक देश और एक मुद्रा के जोखिम से बचा सकते हैं। यह विशिष्ट समाधान, प्रोफेशनल्स द्वारा तैयार किये गये पोर्टफोलियो और थीम-आधारित स्टॉक्स व ईटीएफ उपलब्ध कराता है, जिसे लेने से लेकर फंड ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया डिजिटल है और इस प्रकार, यह सुनिश्चित करता है कि ग्लोबल इन्वेस्टिंग क्षसिम्पल है।

शून्य ब्रोकरेज शुल्क पर करें निवेश

ग्लोबल इन्वेस्टिंग के जरिए एक्सिस सिक्योरिटीज के ग्राहक शून्य ब्रोकरेज शुल्क पर यूएस स्टॉक बाजारों में निवेश कर सकते हैं। प्रीमियम प्लान के साथ, निवेशक कई सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं जैसे - निःशुल्क खाता खोलना, शून्य ब्रोकरेज, और एक वर्ष के लिए निःशुल्क निकासी व अन्य सुविधा।

एक डॉलर से शुरू कीजिए निवेश

इस प्लेटफॉर्म के जरिए निवेशक फ्रेक्शनल इंवेस्टिंग की सुविधा का लाभ उठा कर एक से भी कम स्टॉक में निवेश कर ऊंची कीमतों वाले शेयर्स में न्यूनतम ₹1 (डॉलर) से निवेश शुरू कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ग्राहक 1,000 से अधिक स्टॉक्स व ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं और उसे मैनेज कर सकते हैं। प्रोफेशनल्स द्वारा तैयार किये गये मॉडल पोर्टफोलियोज व थीम-आधारित बास्केट्स में निवेश के लिए अतिरिक्त सुविधा भी है।

निवेशकों का रूझान इंटरनेशनल स्टॉक्स में बढ़ा

एक्सिस सिक्योरिटीज के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बी गोपकुमार का कहना है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय निवेशों की मांग काफी बढ़ी है और विशेषकर टेक-सेवी मिलेनियल्स ने इंटरनेशनल स्टॉक्स में निवेश पर रूचि दिखाई है। उनके ग्लोबल इन्वेस्टिंग का उद्देश्य निवेशकों को दुनिया के सबसे इनोवेटिव कंपनियों व बिजनेसेज का शेयरधारक बनाना है। विशेष प्रकार से तैयार किये गये इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज, थीम-आधारित बास्केट्स व रिसर्च एडवायजरी के जरिए, उन्हें उम्मीद है कि इंटरनेशनल स्टॉक्स में निवेश आसान हो जायेगा और उन्हें सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी।

ग्लोबल ट्रेडिंग के द्वार खुलेंगे

वेस्टेड फाइनेंस के सह-संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विरम शाह का कहना है कि इस साझेदारी से भारतीय खुदरा निवेशकों का दायरा बढ़ेगा। ऐसा देखा गया है कि अब उनकी रूचि दीर्घकालिक निवेश हेतु भौगोलिक रूप से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने में है। उन्हें दृढ़ विश्वास है कि इस प्लेटफॉर्म से अनेक भारतीय निवेशकों के लिए ग्लोबल ट्रेडिंग के द्वार खुलेंगे। इस प्रोडक्ट से विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा और निवेशकों को सीधे यूएस स्टॉक बाजार में निवेश करने की असाधारण क्षमता प्राप्त होगी।

डीलरों को एमएसएमई दर्जा देने पर कर रही विचारः गडकरी

नयी दिल्ली। एजेंसी

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार डीलरों को सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) का दर्जा देने पर विचार कर रही है। इससे डीलर भी एमएसएमई को मिलने वाले लाभ के पात्र हो सकेंगे। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र से जुड़े सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभ और सब्सिडी पाने के लिए अपना पंजीकरण कराना होता है। पंजीकृत एमएसएमई को शुल्क सब्सिडी और कर तथा पूंजीगत सब्सिडी का लाभ मिलता है। पंजीकरण से उन्हें सरकारी ऋणदाताओं तक पहुंच बनाने में मदद मिलती है और वे कम ब्याज दर पर आसान ऋण प्राप्त कर सकते हैं। गडकरी ने मंगलवार को कहा, "जहां तक एमएसएमई की बात है, अब हम डीलरों को भी एमएसएमई का दर्जा देने पर विचार कर रहे हैं। इस पर विचार चल रहा है। इससे उन्हें भी एमएसएमई को मिलने वाले लाभ मिल सकेंगे।" मंत्री ने एक बार फिर बड़े उद्योगों से अपील की कि वे एमएसएमई के बकाये का भुगतान समयबद्ध तरीके से कर दें। उन्होंने कहा, "हम वित्त मंत्रालय से आग्रह कर रहे हैं कि जो उद्योग आयकर को ध्यान में रखते हुये अपने प्रौद्योगिकी केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र, अनुसंधान केंद्र बनाना चाहते हैं, क्या हम उन्हें कुछ और समर्थन देने की स्थिति में हैं। इससे उन्हें और शोध और नवोन्मेषण के लिए प्रेरित किया जा सकेगा।" सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा एमएसएमई मंत्री गडकरी 'निर्माण उपकरण, प्रौद्योगिकी कलपुर्जो तथा संग्राहकों' पर आयोजित एक वर्चुअल प्रदर्शनी को संबोधित कर रह थे। गडकरी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य को हासिल करने के लिये देश को आयात को कम करने और आटोमोबाइल एवं निर्माण कलपुर्जो के क्षेत्र में विनिर्माण को बढ़ावा देने की जरूरत है। उन्होंने उद्योगों से औद्योगिकी शंकुल विकसित करने, प्रौद्यागिकी केन्द्र बनाने, अनुसंधान शालायें खोलने और प्रौद्योगिकी एवं कौशल को अद्यतन करने की अपील की। उन्होंने सभी संबद्ध पक्षों को उनके प्रौद्योगिकी केन्द्र खालने में हर संभव समर्थन का आश्वासन दिया। आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि मंत्री ने अनुसंधान, नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी उन्नयन पर जोर देते हुये इसके लिये आसान विदेशी वित्त और उपयुक्त प्रौद्योगिकी पाने के वास्ते संयुक्त उद्यम बनाने और विदेशी गठबंधन बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार हर तरह के परिवहन को भी विकास करने पर ध्यान दे रही है। जलमार्ग हो अथवा समुद्री परिवहन, रेल, सड़क और हवाई परिवहन को विकसित किया जा रहा है। इससे तमाम तरह की सुविधायें पाने पर होने वाला खर्च कम होगा और उद्योगों को लागत कम करने में काफी मदद मिलेगी।

अर्बन लैडर, मिल्कबास्केट को खरीद सकती है रिलायंसः रिपोर्ट

नई दिल्ली। एजेंसी

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Reliance Industries) अपने ई-कॉमर्स कारोबार को मजबूत करने के लिए ऑनलाइन फर्नीचर रिटेलर अर्बन लैडर (URan Ladder) और मिल्क डिलीवरी फर्म मिल्कबॉस्केट (Milk basket) को खरीद सकती है। जानकारी के मुताबिक, अर्बन लैडर को खरीदने को लेकर रिलायंस की बातचीत एडवांस लेवल पर है। ये डील करीब तीन करोड़ डॉलर में हो सकती है। इस मामले पर रिलांयस, अर्बन लैडर और मिल्कबास्केट पर रॉयटर्स के सवाल का जवाब नहीं दिया।

कोविड 19 महामारी ने ज्यादातर लोगों को अपने घर में रहने के लिए मजबूर कर दिया है। इससे ऑनलाइन शॉपिंग खासकर डेली ग्रॉसरी जैसे दूध आदि की खरीदारी भी शामिल है। एशिया के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस ने मई में ऑनलाइन किराना सेवा जियो मार्ट की शुरुआत की थी। जो भारत में अमेजन डॉट कॉम और वॉलमार्ट इंक को टक्कर देने के लिए शुरू किया गया। मुकेश अंबानी ने बीते महीनों में 20 बिलियन डॉलर से अधिक जुटाए हैं। ये रिलायंस की डिजिटल शाखा जियो प्लेटफॉर्म के लिए किया गया है।

टैक्सपेयर्स के लिए अच्छी खबर

आईटीआर में नहीं देनी होगी यह अहम जानकारी

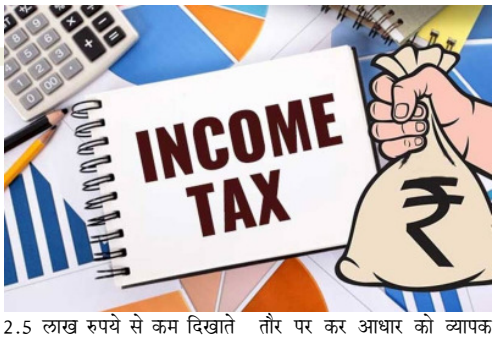

नई दिल्ली। एजेंसी

करदाताओं को अपने आयकर रिटर्न फॉर्म (ITR Form) में बड़े मूल्य के लेनदेन के बारे में जानकारी नहीं देनी होगी। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। घटनाक्रम से जुड़े अधिकारिक सूत्रों ने एक सवाल के जवाब में कहा, 'आयकर रिटर्न फॉर्म में बदलाव का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।' अधिकारियों से इस संबंध में आई कुछ रिपोर्टों के बारे में पूछा गया था। इन रिपोर्टों के मुताबिक 20,000 रुपये से अधिक के होटल भुगतान, 50,000 रुपये से अधिक के जीवन बीमा प्रीमियम भुगतान, 20,000 रुपये से अधिक स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम भुगतान, स्कूल या कॉलेज को साल में एक लाख रुपये से अधिक का अनुदान इत्यादि जैसे वित्तीय लेनदेन की जानकारी देने के लिए रिटर्न फॉर्म का विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है। सूत्रों ने कहा कि वित्तीय लेनदेन के बारे में जानकारी का विस्तार किए जाने का मतलब होगा कि आयकर विभाग को इस प्रकार के ऊंचे मूल्य वाले लेनदेन की जानकारी वित्तीय संस्थान देंगे। आयकर कानून के हिसाब से केवल तीसरा पक्ष ही इस तरह के लेनदेन की जानकारी आयकर विभाग को देता है। आयकर विभाग उस जानकारी के आधार पर यह जांच करता है कि अमुक व्यक्ति ने अपना कर सही से चुकाया है या नहीं। इस जानकारी का उपयोग ईमानदार करदाताओं की जांच के लिए नहीं होता।

आईटीआर फॉर्म में बदलाव का प्रस्ताव नहीं

एक अधिकारी ने कहा, 'आयकर रिटर्न फॉर्म में किसी तरह के बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है। करदाता को आयकर रिटर्न फॉर्म में उसके ऊंचे मूल्य के लेनदेन की जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है।' अधिकारियों ने कहा कि अधिक मूल्य के लेनदेन के माध्यम से करदाताओं की पहचान करना एक बिना दखल वाली प्रक्रिया है। इसके तहत ऐसे लोगों की पहचान की जाती है जो कई तरह का सामान खरीदने में बड़ा धन खर्च करते हैं और उसके बावजूद आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करते या फिर अपनी सालाना आय 2.5 लाख रुपये से कम दिखाते हैं। ऐसे खर्चों में बिजनेस श्रेणी की हवाई यात्रा, विदेश यात्रा, बड़े होटलों में काफी पैसा खर्च करना और बच्चों को महंगे स्कूल में पढ़ाना इत्यादि शामिल है।

बड़े लेनदेन के लिए पहले से है प्रावधान

वित्त मंत्रालय सूत्रों ने कहा कि आयकर कानून में पहले से ही ऊंचे लेनदेन के लिए पैन संख्या या आधार संख्या देने का प्रावधान किया गया है। इस तरह के ऊंचे लेनदेन के बारे में संबंधित कंपनी या तीसरा पक्ष आयकर विभाग को सूचित करता है। यह प्रावधान मुख्य तौर पर कर आधार को व्यापक बनाने के उद्देश्य से किया गया है। सूत्रों का कहना है, 'यह सच्चाई सबके सामने है कि भारत में लोगों का एक छोटा वर्ग ही कर का भुगतान करता है, और वह सब लोग जिन्हें कर का भुगतान करना है वास्तव में कर नहीं चुका रहे हैं।' सूत्रों का कहना है कि ऐसे में आयकर विभाग को कर प्राप्ति के लिये स्वैच्छिक कर अनुपालन पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में तीसरे पक्ष से जुटाई गई वित्तीय लेनदेन का ब्योरा ही बिना किसी हस्तक्षेप के कर अपवंचकों का पता लगाने का सबसे प्रभावी तरीका है।

जीएसटीएन ने जीएसटी करदाताओं के लिये प्रणाली को और बेहतर बनाया

नयी दिल्ली। माल एवं सेवाकर नेटवर्क (जीएसटीएन) ने कहा कि उसने नेटवर्क में ऐसा प्रावधान किया है जिससे कि जीएसटी करदाता को उनके इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के बारे में जानकारी मिल जायेगी और वह जीएसटीआर- 9 को अधिक सुविधा के साथ भर सकेंगे। अब तक जीएसटी प्रणाली में आईटीसी की गणना आपूर्तिकर्ता की बिक्री रिटर्न जीएसटीआर- 1 के आधार पर होती रही है, लेकिन बिल के स्तर पर इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं होती थी। ऐसे में करदाता आईटीसी की गणना को लेकर सवाल उठाते रहे हैं।

जीएसटी के समूचे कप्यूटर नेटवर्क को चलाने वाली कंपनी जीएसटीएन ने एक वक्तव्य जारी कर कहा है कि आपूर्तिकर्ता द्वारा दर्ज प्रत्येक बीजक अथवा बिल को दिखाया जायेगा और प्रत्येक बिल के सामने उसकी गणना को दिखाने की प्रणाली को नेटवर्क में विकसित कर दिया गया है। जीएसटीएन ने जारी वक्तव्य में कहा है, ''जीएसटीएन ने आज नेटवर्क प्रणाली में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था को चालू किया है जिसके जरिये जीएसटी करदाता को उनकी वार्षिक रिटर्न में आने वाले आईटीसी की सही स्थिति के बारे में पता चल जायेगा और इसकी मदद से वह जीएसटीआर-9 को अधिक सुविधा के साथ भर सकते हैं।'' वक्तव्य में कहा गया है कि इस कार्य के लिये जीएसटी पोर्टल के जीएसटीआर- 9 डैशबोर्ड में एक नई टैब 'डानलोड अेबल-8ए डिटेल' की शुरुआत की गई है। यह ब्योरा वित्त वर्ष 2018- 19 से उपलब्ध होगा।

सरकार ने शुरू किया 'स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर चैलेंज', मिलेगा 2.30 करोड़ जीतने का मौका

नई दिल्ली। एजेंसी

देश में आत्मनिर्भर भारत अभियान को और तेज करने के लिए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 'स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर चैलेंज' की शुरुआत की है। इसे 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए माईगॉव पोर्टल पर 18 अगस्त, 2020 से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

इस प्रतियोगिता में सेमी-फाइनल में पहुँचने वाली 100 टीमों को पुरस्कार के रूप में कुल 1.00 करोड़ रुपये रुपये मिलेंगे। फाइनल में पहुँचने वाली 25 टीमों को पुरस्कार के रूप में कुल 1.00 करोड़ रुपये जीतने का मौक़ा मिलेगा। फिनाले में प्रवेश करने वाली 10 टीमों को कुल 2.30 करोड़ रुपये का सीड-फण्ड दिया जाएगा और 12 महीने तक इन्क्यूबेशन सपोर्ट मिलेगा।

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के माइक्रोप्रोसेसर विकास कार्यक्रम के तहत स्वदेशी रूप से डेवलप किए गए माइक्रोप्रोसेसर, शक्ति और वेगा को भी लांच किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के माइक्रोप्रोसेसर डेवपलमेंट कार्यक्रम के तहत आईआईटी मद्रास और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (सीडीएसी) ने ओपन सोर्स आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करते हुए शक्ति (32 बिट) और वेगा (64 बिट) नाम से दो माइक्रोप्रोसेसर डेवलप किए हैं। 'स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर चैलेंज के तहत आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देने के लिए नई टेक्नॉलाजी पर काम करने के लिए स्टार्टअप और छात्रों को आमंत्रित किया गया है। कि वे इन माइक्रोप्रोसेसरों का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे।

स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर चैलेंज' इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की ओर से देश में ध्हहदर्ंूदह म्दबेूस को बढ़ावा देने और डिजिटल प्रौद्योगिकी अपनाने के मामले में सबसे आगे रहने के लिए की पहल का हिस्सा है। यह प्रतिस्पर्धा सभी छात्रों औए स्टार्टअप्स के लिए खुली है। प्रतियोगियों से उम्मीद की जाएगी कि वो स्वदेशी प्रोसेसर आईपी में न केवल बदलाव करें बल्कि इसे इस तरह से इस्तेमाल करें कि ये समाज के लोगों के लिए फायदेमंद हो।

चीन को बड़ा झटका

24 कंपनियां भारत में लगाएंगी मोबाइल फोन प्लांट

नई दिल्ली। एजेंसी

दुनिया में हाहाकार मचा रही कोरोना वायरस महामारी (Covid-19 pandemic) के कारण चीन के प्रति दुनियाभर में गुस्से का माहौल है। दुनिया की कई कंपनियां वहां से अपना बोरिया बिस्तर समेट रही हैं। ऐसी कंपनियों को अपनी तरफ लाने की भारत सरकार की कोशिशें अब रंग लाती दिख रही हैं। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर एप्पल तक के एसेंबली पार्टनर्स ने भारत में निवेश करने में दिलचस्पी दिखाई है।

मोदी सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली कंपनियों के लिए मार्च में कई तरह के प्रोत्साहनों की घोषणा की थी। इसका नतीजा यह हुआ कि करीब दो दर्जन कंपनियों ने भारत में मोबाइल फोन यूनिट लगाने के लिए 1.5 अरब डॉलर के निवेश का वादा किया है। सैमसंग के अलावा फॉक्सकॉन के नाम से जानी जाने वाली कंपनी प्दह ि झ्मेग्दह घ्ह्ल्ल्ि ण्द., विस्ट्रॉन कॉर्प (ैूदह ण्देज.) और पेगाट्रॉन कॉर्प (ईूदह ण्देज.) ने भी भारत ने निवेश में दिलचस्पी दिखाई है। भारत ने साथ ही फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए भी इसी तरह के इंसेंटिव की घोषणा की है। साथ ही कई अन्य सेक्टरों में भी इसे लागू किया जा सकता है। इनमें ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग शामिल है।

वियतनाम पसंदीदा विकल्प

अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते व्यापार तनाव और कोरोना वायरस संक्रमण से कंपनियां अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना चाहती हैं। यही वजह है कि वे चीन के बाहर सप्लाई चेन के विकल्प खोज रही हैं। हालांकि भारत अभी तक इसका ज्यादा फायदा नहीं उठा पाया है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी के एक हालिया सर्वे के मुताबिक इन कंपनियों के लिए वियतनाम सबसे पसंदीदा विकल्प बना हुआ है। इसके बाद कंबोडिया, म्यांमार, बांग्लादेश और थाईलैंड उनकी पसंद है।

10 लाख रोजगार

मोदी सरकार को उम्मीद है कि भारत में अगले 5 साल में 153 अरब डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक्स सामान बनाया जा सकता है और इससे करीब 10 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। नीलकंठ मिश्रा का अगुवाई में क्रेडिट सुइस ग्रुप के विश्लेषकों का मानना है कि इससे अगले 5 साल में देश में 55 अरब डॉलर का अतिरिक्त निवेश आएगा जो देश के इकॉनमिक आउटपुट में 0.5 फीसदी की बढ़ोतरी करेगा। इससे अगले 5 साल में ग्लोबल स्मार्टफोन प्रोडक्शन का अतिरिक्त 10 फीसदी भारत शिफ्ट हो सकता है।

इकॉनमी में बढ़ेगा विनिर्माण का हिस्सा

मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इकॉनमी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी बढ़ाकर 25 फीसदी करने का लक्ष्य रखा है जो अभी 15 फीसदी है। सरकार पहले ही कॉरपोरेट टैक्स में कमी कर चुकी है जो एशिया में सबसे कम है। इसका मकसद देश में नया निवेश आकर्षित करना है। कोरोना वायरस महामारी से देश की इकॉनमी बुरी तरह प्रभावित हुई है और चार दशक से भी अधिक अवधि में यह पहली बार निगेटिव रह सकती है BoFA Secutities में एनालिस्ट अमीश शाह ने कहा कि आउटपुट लिंक्ड इंसेंटिव प्लान मेक इन इंडिया के लिए बड़ी जीत है।

बेस्ट एग्रोलाइफ लिमिटेड ने दर्शाए पहली तिमाही के शानदार परिणाम

राजस्व ने लगाई 77 प्रतिशत की छलांग तो 300 प्रतिशत बढ़ गया मुनाफा

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

बीएसई में सूचीबद्ध कम्पनी, बेस्ट एग्रोलाइफ लिमिटेड ने 30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के शानदार वित्तीय परिणामों की घोषणा की। उल्लेखनीय है कि बेस्ट एग्रोलाइफ लिमिटेड, वैश्विक स्तर पर एग्रो कैमिकल्स के सेक्टर की अग्रणी कम्पनी है और यह भारत की सबसे बड़ी एग्रो-इनपुट्स निर्माता भी है। अपनी दीर्घकालिक वित्तीय प्राथमिकताओं के मामले में कम्पनी अपनी जगह पर स्थिर है, वे प्राथमिकताएं जो कि एक तीन आयामी (थ्री डायमेंशनल) सोच रखती है और जिसके अंतर्गत मुख्यतः कैपिटल एलोकेशन (पूंजी निर्धारण), आमदनी और वृद्धि ध्यान केंद्रित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 20-21 की पहली तिमाही के अनऑडिटेड परिणामों के अनुसार कम्पनी का सकल राजस्व 204.18 करोड़ रुपये (19-20 की पहली तिमाही में) की तुलना में 363.04 करोड़ रुपये तक बढ़ गया, यह करीब 77 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी है। यदि तरह कम्पनी का मुनाफा लगभग तिगुना होते हुए 5.46 करोड़ रुपये (वित्तीय वर्ष 19-20 की पहली तिमाही) की तुलना में 16.21करोड़ रुपये (वित्तीय वर्ष 20-21 की पहली तिमाही) पर पहुंचा, जबकि ईपीएस 6.03 रुपये (वित्तीय वर्ष 19-20 की पहली तिमाही) से बढ़कर 6.95 रुपये (वित्तीय वर्ष 20-21 की पहली तिमाही) तक पहुंच गया।

इस उपलब्धि के बारे में विस्तार से बताते हुए, श्री विमल कुमार, मैनेजिंग डायरेक्टर, बेस्ट एग्रोलाइफ लिमिटेड ने कहा-'हमने अपने लक्ष्यों को एकदम स्पष्ट रखा और कम्पनी कम्पनी इन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में काम करेगी। इसके अंतर्गत प्रमुख फोकस दीर्घकालिक ईपीएस वृद्धि को पाने का होगा।' इस प्रक्रिया को पूरे आर्थिक चक्र में होने वाली इंक्रीमेंटल अर्निंग्स (वृद्धि सम्बन्धी आमदनी) द्वारा सहयोग मिलता रहेगा। इसके साथ ही हम आरओसीई व आरओई में महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी का भी अनुमान लगा रहे हैं, जो कि हमारे विभिन्न अभियानों द्वारा संचालित होंगे। आरओसीई तथा आरओई के संदर्भ में प्रोजेक्ट टारगेट्स वित्तीय वर्ष 22 में क्रमशः 32.78 प्रतिशत और 24 प्रतिशत हैं।

बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड को कनाडा सरकार द्वारा मान्यता दी गई

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड की सहायक कंपनी बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज कनाडा इंकॉर्पोरेटेड को आरसीएमपी के कनाडाई आपराधिक रियल टाइम आइडेंटिफिकेशन सर्विसेज (सीसीआरटीआईएस) द्वारा रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (ण्इ), कनाडा सरकार के लिए फिंगर प्रिंटिंग सर्विसेज चलाने के लिए मान्यता दी गई है। यह परियोजना मुख्य रूप से कनाडा में आरसीएमपी, कनाडा सरकार की ओर से रियल टाइम फिंगर प्रिंटिंग कैप्चर करने के लिए बनाई गई है।

बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज कनाडा इंकॉर्पोरेटेड को एक व्यक्तिगत फिंगर प्रिंटिंग सेवा प्रदाता के रूप में प्रमाणित किया गया है। नए प्रवासियों को छात्रों, स्थायी निवासियों, नागरिकता, नौकरी चाहने वालों, कनाडा सरकार के कर्मचारियों और अन्य श्रेणियों के रूप में यह सेवाएं प्रदान की जाएंगी। आवेदक कनाडा में 9 बीएलएस कार्यालयों में अपने आवेदन जमा करते हैं। कुल मिलाकर आरसीएमपी फ़िंगरप्रिंट काउंट्स में सालाना कनाडा और कनाडा के बाहर से लगभग 5 मिलियन आवेदन आने की संभावना है। हाल ही में आरसीएमपी में हुए नीतिगत परिवर्तनों के आधार पर यह आंकड़ा काफी बढ़ने की उम्मीद है। विश्व स्तर पर सरकारों, और राजनयिक मिशनों के लिए वीजा, पासपोर्ट, सत्यापन और नागरिक सेवाओं के विशेषज्ञ सेवा प्रदाता, बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज ने हाल ही में 30 जून 2020 को समाप्त हुई पहली तिमाही के लिए संयुक्त वित्तीय परिणामों की घोषणा की। वित्तीय वर्ष 21 (इ्र21) की पहली तिमाही अप्रैल से जून तक का ऑपरेशनल रेवेन्यू 52.15 करोड़ रुपए रहा। कोविड-19 महामारी के कारण, अप्रैल और मई 2020 के दौरान वीजा और कांसुलर सेवाओं के संचालन को बंद कर दिया गया था। कांसुलर सेवाओं के संबंध में सीमित संचालन को जून 2020 के दौरान आंशिक रूप से फिर से शुरू किया गया था।

सरकार से नागरिक डगवर्नमेंट टू सिटीजन (जी-टू-सी). सेवाओं के क्षेत्र में एक जानेमाने लीडर के रूप में बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में बेंचमार्क स्थापित करने के लिए प्रतिष्ठा अर्जित की है। कंपनी द्वारा दुनिया भर में स्थित अपनी ग्राहक-सरकारों के पसंदीदा भागीदार के रूप में खुद को स्थापित करने के लिए लगातार अपनी सेवाओं को उत्कृष्ट बनाने का प्रयास करते हुए पिछले बारह वर्षों में तेजी से वृद्धि की है। तेजी से विकास करने वाले बाजारों में अपनी प्रमुख स्थिति और व्यापार के अवसरों का लाभ उठाते हुए, संगठन अब जी-टू-सी बिजनेस में विश्व स्तर पर परिवर्तनकारी विकास की ओर अग्रसर है।

कंपनी के संयुक्त प्रबंध निदेशक श्री शिखर अग्रवाल ने भविष्य की योजनाओं पर टिप्पणी करते हुए कहा, 'चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन हटाने के साथ ही कंपनी ने भी अपने कार्यालय को चरणबद्ध तरीके से फिर से खोलना शुरू कर दिया है, जिसमें सरकार और स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा दी जा रही सलाह के मुताबिक सीमित स्टाफ के साथ सोशल डिस्टन्सिंग का ध्यान रखते हुए काम किया जा रहा है। कई राजनीतिक, वित्तीय और आर्थिक प्रणालियों में स्थित ग्राहक सरकारों, विविध नियमों और सांस्कृतिक परम्परों का पालन करने के साथ, बीएलएस इंटरनेशनल गतिशील आवश्यकताओं की एक विस्तृत श्रृंखला को पूरा करने में सक्षम रहा है। उन्होंने वैश्विक बाजार में अपने सभी कार्यक्षेत्रों में सफलता सुनिश्चित करने के लिए इन चुनौतियों को प्रभावी ढंग से संबोधित किया है। उनके कुछ प्रतिष्ठित ग्राहकों में विदेश मंत्रालय - भारत सरकार, विदेश मंत्रालय-संयुक्त अरब अमीरात और स्पेन सरकार शामिल हैं।'

धूप-अगरबत्ती कारोबार में सालाना 15 प्रतिशत की वृद्धि :उद्योग

नयी दिल्ली। एजेंसी

कोविड-19 महामारी के बीच सालाना पंद्रह हजार करोड़ रुपये के देश के धूप-अगरबत्ती कारोबार में 15 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हो रही है और निवेशक आकर्षित हो रहे हैं। श्रम गहन इस उद्योग का कहना है कि कारोना वायरस संक्रमण के इसमुश्किल वक्त में भी लोगों की आस्था, पूजा पर किसी महामारी का अधिक प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है और आम लोगों में पूजा सामग्रियों की मांग बढ़ी भी है। अगरबत्ती कंपनी मोड रिटेल एंड मार्केटिंग के निदेशक संजीव नायर ने एक बयान में कहा कि अगरबत्ती और धूप का घरेलू बाजार 15,000 करोड़ रुपये का है और सालना 15 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है।'' उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र नया निवेश आकर्षित कर रहा है। उद्योग के अनुसार देश में अगरबत्तियों की मौजूदा मांग 3,000 टन की है जबकि आपूर्ति इसकी आधी है। बाकी माल चीन और वियमतनाम जैसे देशों से आता रहा है। नायर ने बताया कि धूप-अगरबत्ती उद्योग में निवेशक आकर्षित हो रहे हैं। उन्होंने कहा मोड रिटेल के प्रमुख ब्रांड प्रभु श्रीराम (पीएसआर) ब्रांड में ही देश विदेश के निवेशकों ने कुल लगभग 100 करोड़ रुपये के निवेश का निवेश किया है या प्रतिबद्धता जतायी है।निवेश के कई समझौतों का अंतिम रूप दिया जा रहा है पीएसआर का इरादा अगले दो वर्षों में अगरबत्ती कारोबार में महत्वपूर्ण बाजार हिस्सेदारी हासिल करने की है।

भारत ने राजनयिक चैनलों के जरिये रक्षा निर्यात को प्रोत्साहन की रूपरेखा बनाई

नयी दिल्ली। एजेंसी

सरकार ने देश में विनिर्मित सैन्य उपकरणों तथा हथियारों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए एक रूपरेखा तैयार की है। रक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को कहा कि भारत में बने रक्षा उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन के लिए राजनयिक चैनलों का इस्तेमाल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसी महीने एक बड़े नीतिगत फैसले की घोषणा करते हुए कहा था कि चरणबद्ध तरीके से 101 सैन्य उपकरणों और हथियारों के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके पीछे मकसद घरेलू रक्षा उद्योग को प्रोत्साहन देना है। रक्षा उत्पादन विभाग में सचिव राज कुमार ने सोमवार को एक वेबिनार में कहा कि घरेलू रक्षा उद्योग मित्र देशों के प्रतिनिधियों के साथ वेब परिचर्चा करेगा, जिससे यह पता चल सकेगा कि उन्हें किस

तरह के उत्पादों और मंचों की जरूरत है।

कुमार ने कहा, "हम देशों के आधार पर उत्पादों, हथियारों ओर मंचों का प्रोफाइल बना रहे हैं। इससे हमें पता चल सकेगा कि हमारे मित्र देशों को किन उत्पादों की जरूरत है। हम उद्योग की अगुवाई में वेब परिचर्चा की योजना बना रहे हैं।" उन्होंने कहा, "उस देश के रक्षा सहचारी, हमारे रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (डीपीएसयू) और उद्योग उसके बाद तय करेंगे कि हमारे पास क्या है जिसके निर्यात को प्रोत्साहन दिया जा सकता है।" कुमार ने कहा कि सरकार अपने रक्षा सहयोगियों, दूतावासों तथा राजनयिक चैनलों के जरिये निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए उद्योग के साथ खड़ी है। घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने नौ अगस्त को 101 रक्षा उपकरणों और हथियारों के आयात पर अंकुश लगाने की घोषणा की थी। कुमार ने कहा कि जल्द उन रक्षा उत्पादों की दूसरी सूची भी अधिसूचित की जाएगी जिनके आयात पर अंकुश लगाया जाना है।

उद्योग मंडल फिक्की द्वारा आयोजित वेबिनार 'आर्मी मेक प्रोजेक्ट्स 2020' को संबोधित करते हुए कुमार ने कहा, "यह पहली सूची है जिसकी हम समीक्षा कर रहे हैं। जल्द दूसरी सूची भी आएगी।" उन्होंने उद्योग से कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए जल्द निवेश को आगे आएंगे। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एक बार बोली लगाने वाली सफल कंपनियां रक्षा उपकरण उत्पादन के चरण में पहुंचेंगी, उसके बाद विभाग उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के रक्षा गलियारा प्राधिकरणों से उनका ब्योरा साझा करेगा। वे आपकी इकाइयों को अपने राज्य में आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।

दुबई-सिंगापुर की तर्ज पर गुजरात में बनेंगी 70 मंजिला से ऊंची इमारतें

अहमदाबाद। एजेंसी

गुजरात सरकार ने राज्य में इन्फ्रास्ट्रक्चर को गति देने के लिए एक अहम निर्णय लिया। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्य के पांच मेगा शहरों में 70 मंजिल से अधिक ऊंची इमारतें बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह फैसला इस मायने में अहम है कि इससे गुजरात में यूएई और सिंगापुर जैसे देशों की तर्ज पर अट्टालिकाएं बनने का रास्ता साफ हो गया है। यूएई और सिंगापुर को अपने शानदार इन्फ्रास्ट्रक्चर और गगनचुंबी इमारतों के लिए जाना जाता है। ये इमारतें अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट और गांधीनगर में बनेंगी। राज्य सरकार ने एक बयान में कहा कि इस फैसले का लक्ष्य गुजरात को यूएई और सिंगापुर की तरह दुनिया के नक्शे पर स्थापित करना है। यह फैसला न केवल गुजरात में गगनचुंबी इमारतों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा बल्कि इससे इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में राज्य की क्षमताओं का भी प्रदर्शन होगा। नए नियमों से राज्य में 70 मंजिल से ऊंची इमारतों का निर्माण हो सकेगा। पहले राज्य में केवल 22-23 मंजिला इमारतें बनाने की ही अनुमति थी।

लोगों को मिलेगा रोजगार

इस तरह की गगनचुंबी इमारतों को बनाने के लिए सीजीडीसीआर-2017 में प्रावधान किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि गगनचुंबी इमारतों के निर्माण से शहरी इलाकों में बढ़ रही आबादी की आवास जरूरतें पूरी होंगी और लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। इन बहुमंजिला इमारतों का उपयोग आवासीय, कमर्शल और इंटरटेमेंट प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा।

सैमसंग की अगले पांच साल में

देश में 3.7 लाख करोड़ रुपये मूल्य के मोबाइल फोन उत्पादन की योजना

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

सैमसंग इंडिया की अगले पांच साल में देश में 3.7 लाख करोड़ रुपये के मूल्य मोबाइल फोन विनिर्मित करने की योजना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अपनी योजना साझा की है। देश में फोन विनिर्माण को तेज करने के लिए सरकार ने 'विनिर्माण के लिए पहल' (पीएलआई) योजना शुरू की है। कंपनी इस योजना के तहत 15,000 रुपये से अधिक मूल्य वाले 2.2 लाख करोड़ रुपये मूल्य के स्मार्टफोन विनिर्मित करेगी। एक अधिकारी ने नाम ना छापने शर्त पर कहा, " सैमसंग की अगले पांच साल में 50 अरब डॉलर (3.7 लाख करोड़ रुपये) मूल्य के फोन विनिर्माण की योजना है। इसमें से 30 अरब डॉलर मूल्य के स्मार्टफोन का उत्पादन पीएलआई योजना के तहत किया जाएगा।" हालांकि इस संबंध में सैमसंग ने कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। ना ही भेजे गए ई-मेल का जवाब दिया है। सैमसंग के अलावा कई घरेलू-वैश्विक मोबाइल फोन विनिर्माता कंपनियों ने सरकार की पीएलआई योजना के तहत फोन विनिर्माण के लिए आवेदन किया है। इसमें विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन, फॉक्सकॉन और होन हाई जैसी वैश्विक कंपनियों के साथ-साथ लावा, डिक्सन, माइक्रोमैक्स, पेजेट इलेक्ट्रॉनिक्स, सोजो और ऑप्टिमस इत्यादि शामिल हैं। सरकार को पीएलआई योजना के तहत अगले पांच साल में देश में 11 लाख करोड़ रुपये मूल्य के मोबाइल फोन उत्पादन की उम्मीद है।

कोरोना और चीनी संघर्ष से बढ़ी भारतीय खिलौनों की डिमांड

नई दिल्ली। एजेंसी

कोरोना की वजह से स्कूल बंद हैं। गैर जरूरी आउटडोर एक्टिविटी पर रोक है। बच्चे घरों में ही पढ़ाई और खेलकूद रहे हैं। इसका सकारात्मक असर खिलौना व्यापार पर पड़ा है। चीन और भारत के बीच चल रहे संघर्ष की वजह से चाइनीज खिलौनों की मांग घटी है। इसका लाभ भी भारतीय खिलौना निर्माताओं को मिल रहा है। 'द टॉय असोसिएशन ऑफ इंडिया' (TTAI) के प्रेसिडेंट अजय अग्रवाल ने कहा कि चीन से माल नहीं आ रहा है, तो देसी निर्माताओं की मांग हो रही है। चीन के प्रति हिन्दुस्तानी ग्राहकों और कारोबारियों का व्यवहार बदला है। बच्चे घरों में है, तो इनडोर गेम्स, पजल, बोर्ड गेम्स, कैरमबोर्ड और प्लास्टिक के खिलौनों की डिमांड आ रही है।

अजय अग्रवाल ने बताया कि अब भारतीय खिलौना निर्माताओं ने अपने माल की क्वालिटी और प्रॉडक्शन बढ़ाने पर जोर देना शुरू कर दिया है। इससे डोमेस्टिक मार्केट में इंडियन ट्रेडर्स का शेयर बढ़ेगा और एक्सपोर्ट में भी

कदम तेजी से बढ़ेंगे। अभी भारत से अन्य देशों में एक्सपोर्ट में काफी गुंजाइश है। इससे हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार भी अब भारतीय निर्माताओं को उठाने में मदद कर रही है।

दिल्ली के आसपास ही 1000 यूनिट

ऊऊँध प्रेसिडेंट के मुताबिक, दिल्ली और आसपास के शहरों में ही खिलौनों से जुड़ी छोटी-बड़ी मिलाकर करीब 1000 यूनिट हैं। सरकार सहयोग करेगी, तो खिलौना इंडस्ट्री में ही रोजगार के बड़े अवसर हैं। यहां अकुशल मजदूरों को भी काम मिल जाता है। इसमें मशीनों से कम, हाथों से अधिक काम होता है। दिल्ली में बवाना, पटपड़गंज, यूपी में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और हरियाणा में सोनीपत और फरीदाबाद में भी खिलौनों की फैक्ट्रियां हैं। यहां सोफ्ट टॉय, वुडन टॉय और प्लास्टिक टॉय समेत हर तरह के खिलौने बनते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक टॉय की काफी डिमांड

बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक टॉय ज्यादा पसंद हैं। अजय अग्रवाल का कहना है कि अगले 4-5 महीनों में इलेक्ट्रॉनिक टॉय मैन्यफैक्चर्स की संख्या बढ़ जाएगी। अभी देश में बैट्री और बिजली से चलने वाले खिलौनों के निर्माता कम है। चीन से इंपोर्ट कम होने की वजह से देशी निर्माताओं को बेहतर अवसर मिल रहे हैं। अब तो साहिबाबाद और बवाना में राइडऑन टॉय बनने लगे हैं। पूरी कोशिश है कि खिलौना इंडस्ट्री में चीनी शेयर को घटाकर भारत के शेयर को बढ़ाया जाए।

पूर्व, पश्चिम के उद्योगों को दक्षिण भारत से जोड़ने को 4,000 किमी. के ढुलाई गलियारे बनाएगा रेलवे

नयी दिल्ली। एजेंसी

रेलवे देश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के औद्योगिक क्षेत्रों को दक्षिण भारत से जोड़ने के लिए करीब 4,000 किलोमीटर के प्रतिबद्ध मालढुलाई गलियारों (डीएफसी) का निर्माण करेगा। इसमें देश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को दक्षिण भारत के साथ ओड़िशा और आंध्र प्रदेश के प्रमुख बंदरगाहों के जरिये जोड़ा जाएगा। इन गलियारों पर एक दस्तावेज से यह जानकारी मिली है। प्रस्तावित डीएफसी रेलवे की अगली बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का हिस्सा हैं इनमें....खड़गपुर (प. बंगाल) से विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) को जोड़ने वाला 1,115 किलोमीटर का पूर्वी तटीय गलियारा, भुसावल-नागपुर-खड़गपुर-दानकुनी (कोलकाता के पास) मार्ग को जोड़ने वाला 1,673 किलोमीटर का पूर्व-पश्चिम गलियारा और 195 किलोमीटर का राजखर्सवान-कालीपहाड़ी-अंडल (प. बंगाल) को जोड़ने वाला गलियारा शामिल हैं। तीसरा 975 किलोमीटर का उत्तर दक्षिण उप गलियारा है। यह विजयवाड़ा-नागपुर-इटारसी (मध्य प्रदेश) मार्ग को जोड़ेगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.(डीएफसीसीआईएल) जल्द इन गलियारों के सर्वे का काम शुरू करेगी। वह इस प्रक्रिया को एक साल में पूरा करेगी। ये गलियारे ओड़िशा के पारादीप, धामरा, गोपालपुर बंदरगाहों तथा आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम, गंगावरम, काकीनाडा, कृष्णापत्तनम और मछलीपत्तनम बंदरगाहों को संपर्क उपलब्ध कराएंगे। इनसे माल की ढुलाई तेज हो सकेगी और रेलवे नेटवर्क की क्षमता बढ़ सकेगी।

हरतालिका तीज का पर्व दांपत्य जीवन की खुशहाली की कामना से जुड़ा है। साथ ही यह पर्व हमें अपने घर-परिवार और पारंपरिक मूल्यों से भी जोड़ता है। यही वजह है कि वर्तमान कोरोना काल में इस पर्व की महत्ता और ज्यादा बढ़ गई है। आइए, मन में छाने वाली हर निराशा को मिटाकर इस पारंपरिक पर्व को हम अपनों के संग उमंग-उल्लास से मनाएं।

हरतालिका तीज
खुशहाल घर-परिवार की कामना

आवरण कथा
डॉ. मोनिका शर्मा

पर्व-त्योहारों को मनाने से जुड़ी खुशियों के मायने और अपनों के साथ की अहमियत, कोरोना काल ने हमें खूब समझा दी है। परिवार और परंपरा से जोड़कर रखने वाले पर्व, मन-जीवन को सुख देते हैं, यह पाठ भी सबने पढ़ लिया है। अपनों की कुशल कामना का ऐसा ही पर्व है, हरतालिका तीज, जिसे विवाहित महिलाएं ही नहीं, कुछ अविवाहित कन्याएं भी उल्लास के साथ मनाती हैं। माना जाता है कि इस दिन मां गौरी (पार्वती) और भगवान शिव की पूजा सौभाग्यदायिनी होती है। इसीलिए शादी-शुदा महिलाएं दांपत्य जीवन की खुशियों के लिए आराधना करती हैं तो अविवाहित लड़कियां अच्छा जीवन साथी पाने की कामना के साथ पूजा करती हैं।

आत्मीयता व्यक्त करने का माध्यम

हरतालिका तीज जैसे पर्व, स्नेह और भावनात्मक भावों को व्यक्त करने का माध्यम हैं। यह व्रत-पर्व महिलाओं के मन में मौजूद पारिवारिक और सामाजिक आत्मीयता को महसूस करने का अवसर भी देता है। इस आत्मीयता में अपने घर-परिवार की खुशियों की चाह सबसे ऊपर होती है। भारतीय समाज में महिलाएं हमेशा से खुद से भी अधिक अपनों की खुशियों की कामना करती हैं। तभी तो पूरी निष्ठा के साथ परिवार की खुशी और सुख-समृद्धि को कायम रखने में जुटी भी रहती हैं। उनकी इच्छा होती है कि दांपत्य जीवन हर हाल में खुशियों से सराबोर रहे और उनके अपने, करीबी हर संकट से सुरक्षित रहें। कोरोना काल में भी अपनों का संबल बनने और उनके स्वास्थ्य संभालने के मोर्चे पर महिलाएं पीछे नहीं रहीं। इस आपदा के दौर में हर पल घर में मौजूद छोटे-बड़े सदस्यों से जुड़े काम-काज से उनकी आपा-धापी बढ़ी, रोज की जिम्मेदारियों के साथ सबकी सेहत ठीक रखने का दायित्व भी बढ़ गया। लेकिन फिर भी वे इस संकट काल में अपनों की संभाल-देखभाल में हर पल व्यस्त रहीं और अब भी हैं। ऐसे में हरतालिका तीज का आगमन उनके मन को, उनकी भीतर की सकारात्मक ऊर्जा को और बढ़ा देगा। हर बार की तरह इस बार भी वे ईश्वर से अपनों की खुशियों और मंगलकामना का वर मांगेंगी। ऐसा करने से उनके भीतर यह भाव प्रबल होगा कि मेरे अपने सुरक्षित रहेंगे और आगे सब कुछ ठीक होगा।

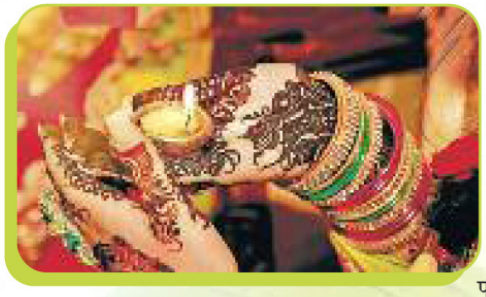

जीवन में भरता उल्लास

हरतालिका तीज जैसे लोकपर्व, मन में उल्लास जगाने वाली ऊर्जा भी साथ लाते हैं। मन का नहीं, घर के आंगन का भी माहौल बदलते हैं। कोरोना संकट की घरबंदी में यह बदलाव बहुत महत्व रखता है। इन दिनों घर के आंगन तक सिमटी सभी सदस्यों की जिंदगी नीरस और थकी-सी हो रही है। वहीं महिलाओं के लिए भाग-दौड़ बढ़ गई है। ऐसे में इस पारंपरिक पर्व के जरिए उन्हें अपने लिए समय मिलेगा। यह पर्व उनके मन को नए रंगों से भर देगा। मेहंदी, चूड़ियां, नई साड़ी पहनकर-सज-संवरकर जब वे पूजन करेंगी तो उनके मन में खुशियों का एक इंद्रधनुष उभर आएगा।

बढ़ता है परिवार से जुड़ाव

यह त्योहार दांपत्य जीवन के भावनात्मक बंधन को और मजबूती देने वाला है ही, साथ ही नई और पुरानी पीढ़ी के बीच सेतु का काम भी करता है। ऐसे त्योहार परिवार को जोड़ते हैं, परंपरागत मूल्यों को सहेजते हैं। कोरोना संकट में इन जीवन मूल्यों और भावनात्मक जुड़ाव के पहलुओं की अहमियत फिर पुख्ता हुई है। जो सीधे-सीधे यही समझाती है कि जिंदगी के हर मोड़ पर अच्छे-बुरे दिन आते-जाते रहते हैं लेकिन किसी भी मुश्किल और कठिन परिस्थिति में परिवार ही इंसान को थामता है। तकलीफदेह दौर में जीवन साथी और परिवार के साथ से बढ़कर कोई संबल नहीं होता। अपनों का साथ, हर तरह की परिस्थितियां झेलने का साहस और उनसे बाहर आने का भरोसा देता है। ऐसे में अपनों की कुशल कामना का पर्व हरतालिका तीज, पारिवारिक व्यवस्था में हमारे विश्वास को सींचता है।

हावी न हो निराशा

यूं तो हरतालिका तीज पर आस-पड़ोस की महिलाएं एकत्रित हो लोकगीत गाती हैं, सज-धज कर सखियों संग उत्साह-उल्लास के साथ व्रत के अनुष्ठान को पूरा करती हैं। लेकिन इस बार यह पर्व कोरोना वायरस की महामारी से बचाव के लिए एहतियात बरतते हुए मनाया जाएगा। यानी इस बार हरतालिका तीज के पारंपरिक उत्सव में सखियों का साथ नहीं मिल पाएगा। लेकिन यह सोचकर निराश क्या होना? इस संकट में पूरा परिवार तो आपके साथ ही रहेगा। उनका साथ तीज पर्व को और जीवंत बनाने वाला साबित होगा। हर हालात में अपने जीवट से जिंदगी को गतिशील रखने वाली स्त्रियां इन परिस्थितियों में भी परंपरा के रंगों को सहेजकर, इस पर्व को मन से जरूर मनाएंगी।

शिव-पार्वती सा दांपत्य जीवन

वैवाहिक जीवन की खुशहाली की कामना से जुड़ा यह पर्व भगवान शिव और मां गौरी को समर्पित है। उनसे खुशियां और स्नेह-साथ का वर मांगने का पर्व है। इसीलिए महिलाएं हरतालिका तीज पर शिव-पार्वती का वंदन-पूजन कर सफल और सुदृढ़ वैवाहिक जीवन का वर मांगती हैं। शिव-पार्वती अटूट दांपत्य और समर्पण भरे साथ का प्रतीक हैं। इसीलिए उनके आदर्श दांपत्य जीवन को पूजते हुए स्त्रियां यह कामना करती हैं कि जीवनसाथी से स्नेह और साथ भी यूं ही कायम रहे। यह सोच बताती है कि हमारे देश में महिलाएं अपने जीवन साथी के लिए कितना गहरा जुड़ाव रखती हैं।

डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज ने भारत के बाजार में उतारी कोविड- 19 के इलाज की दवा

नई दिल्ली। एजेंसी

डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज ने बुधवार को कोरोना वायरस महामारी के इलाज की दवा अविगन (फेविपिराविर) टैबलेट बाजार में उतारने की घोषणा की। यह दवा कोविड-19 के हल्के से लेकर सामान्य संक्रमण के इलाज में इस्तेमाल के लिये है। दवा कंपनी ने शेयर बाजारों को भेजी नियामकीय सूचना में कहा है, ''फूजीफिल्म टोयामा केमिकल कंपनी लिमिटेड के साथ हुये वैश्विक लाइसेंसिंग समझौते के तहत डॉ. रेड्डीज को अविगन (फेविपिराविर) 200 मिलीग्राम की गोली का भारत में विनिर्माण, बिक्री और वितरण का विशेष अधिकार मिला है।'' डॉ. रेड्डीज ने कहा है कि उसकी दवा 'अविगन' को भारत के दवा महानियंत्रक (डीसीजीआई) से कोविड- 19 के हल्के से लेकर मध्यम रूप से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिये मंजूरी मिली है। डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज के ब्रांडेड मार्केट्स (भारत और उभरते बाजारों) के सीईओ एम वी रमन्ना ने कहा, ''हमारे लिये उच्च गुणवत्ता, बेहतर क्षमता, वहनीयता और बीमारी का बेहतर प्रबंधन सबसे पहली प्राथमिकता है। मेरा मानना है कि अविगन टैबलेट भारत में कोविड- 19 से प्रभावित मरीजों के लिये प्रभावी इलाज उपलब्ध करायेगी।''

कोरोना से भारत का क्या है हाल?

पिछले चौबीस घंटों में फिर से 65 हजार से ज्यादा नए मामले आए। इसके साथ ही, भारत में अब तक कुल कोविड-19 महामारी के शिकार हुए लोगों की तादाद बढ़कर 27,66,626 पर पहुंच गई है। हालांकि, इलाज के बाद इस महामारी से मुक्ति पाने वालों की तादाद भी पिछले चौबीस घंटों में 60,455 रही। देशभर में अब तक कुल 20,36,703 मरीज रिकवर कर चुके हैं। इस तरह देखें तो देश में कुल ऐक्टिव केस सिर्फ 6,76,387 हैं। कोरोना ने अब तक भारत में 53,015 लोगों की जानें ले ली है। पिछले चौबीस घंटों में कुल 1,090 कोविड-19 मरीजों ने दम तोड़ा है।

भारत में शुरू होने जा रही है टोयोटा की एसयूवी URan Cruiser की बुकिंग- 22 अगस्त को होगी लॉन्च

नई दिल्ली। Toyota Kirloskar Motor की अपकमिंग एसयूवी Toyota URan Cruiser की बुकिंग 22 अगस्त यानी लॉन्चिंग के बाद शुरू होने वाली है। अर्बन क्रूजर की लॉन्चिंग में अब महज 3 दिन का समय रह गया है ऐसे में कंपनी अब इसकी लॉन्चिंग के बाद कंपनी इसकी बुकिंग्स भी शुरू करने वाली है। अभी हाल ही में अर्बन क्रूजर के लिए लॉन्चिंग कैम्पेन शुरू किया था जिसका नाम 'Respect' रखा गया था।

टोयोटा अर्बन क्रूजर मारुति विटारा ब्रेजा का ही रीबैज मॉडल है जिसे नए नाम और खासियतों के साथ मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है। कंपनी ने अर्बन क्रूजर को ख़ास तौर से युवाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया है। इसकी स्टाइलिंग से लेकर फीचर्स तक में युवाओं की पसंद का ख़ास ख्याल रखा गया है। इसे ज्यादा से ज्यादा स्पोर्टी लुक देने के लिए कंपनी ने इसमें काफी सारे बदलाव किए हैं।

इंजन और पावर: जानकारी के मुताबिक़ अर्बन क्रूजर में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है, जो 105PS की पावर और 138Nm का टॉर्क जेनरेट करेगा। ये इंजन 5 स्पीड मैनुअल और 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स से लैस होगा। इस कार में माइल्ड तकनीक भी दी जाएगी जिससे ये अच्छा-खासा माइलेज भी जेनरेट करेगी।

एक्सटीरियर: एक्सटीरियर की बात करें तो Toyota URan Cruiser में ट्विन पॉड हेडलैंप, 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील, ट्विन स्लेट ग्रिल, फॉक्स स्किड प्लेट क्रोम फ्रेम जैसे एक्सटीरियर फीचर्स देखने को मिलेंगे।रिपोर्ट के मुताबिक इस कार की कीमत 8 लाख से शुरू हो सकती है।

टोयोटा अर्बन क्रूजर की बात करें तो ये मारुति सुजुकी और टोयोटा के कोलैबरेशन का दूसरा प्रोडक्ट होगा जिसे रीबैज करके तैयार किया गया है। रीबैजिंग में गाड़ी का नाम तो बदला ही गया है साथ ही इसमें कई बड़े बदलाव भी किए गए हैं, जिससे ये विटारा ब्रेजा से हटकर बेहतरीन प्रोडक्ट बन सके। कंपनी की ये स्ट्रैटजी मौजूदा हालात को देखते हुए कारगर साबित हो सकती है। खासकर ग्राहकों के लिए भी ये एक अच्छा मौक़ा है, क्योंकि उन्हें भी किफायती कीमत में नया प्रोडक्ट मिलेगा।

प्योर ईवी ने इलेक्ट्रिक स्कूटर 'ईट्रांसप्लस उतारा, दाम 56,999 रुपये

नयी दिल्ली। एजेंसी

इलेक्ट्रिक वाहन स्टार्टअप प्योर ईवी ने अपना नया बिजलीचालित स्कूटर मॉडल 'ईट्रांस प्लस' पेश किया है। इसकी शोरूम कीमत 56,999 रुपये है। यह स्टार्टअप कंपनी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-हैदराबाद (आईआईटी-हैदराबाद) ने गठित की है। कंपनी ने सोमवार को बयान में कहा कि यह उसका पांचवां उत्पाद है। इसमें 1.25 केडब्ल्यूएच पोर्टेबल बैटरी लगी है। प्योर ईवी आईआईटी-हैदराबाद की स्टार्टअप प्योर एनर्जी की इलेक्ट्रिक वाहन इकाई है। प्योर एनर्जी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) रोहित वढ़ेरा ने कहा, ''हम मध्यवर्गीय भारतीय उपभोक्ताओं की जरूरतों के अनुरूप लगातार नवोन्मेषण करते हैं। कोविड-19 महामारी के दौर में लोग अपना निजी वाहन खरीदना चाहते हैं। लोग ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहते हैं जिसका दाम कम हो।'' उन्होंने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि ईट्रांसप्लस उन अधिकतर ग्राहकों की जरूरत को पूरा करेगा जो रोजाना के इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना चाहते हैं।

चीन, कोरिया से कास्टिक सोडा आयात पर तीन महीने पर और लगेगा डंपिंगरोधी शुल्क

नयी दिल्ली। एजेंसी

सरकार ने चीन और कोरिया से कास्टिक सोडा के आयात पर डंपिंग रोधी शुल्क सोमवार को तीन महीने के लिए और बढ़ा दिया। स्थानीय उद्योग को बचाने लिए यह कदम उठाया गया है। वाणिज्य मंत्रालय के तहत कार्य करने वाली जांच इकाई व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीआर) ने इस रसायन के चीन और कोरिया से आयात पर मौजूदा डंपिग रोधी शुल्क को आगे बढ़ाने की अनुशंसा की थी। डंपिंग रोधी शुल्क को लेकर डीजीटीआर स्थानीय उद्योगों की शिकायत के आधार पर जांच करता है और अपनी सिफारिश वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को भेजता है। बाद में मंत्रालय शुल्क लगाने का अंतिम निर्णय लेने के लिए इसे वित्त मंत्रालय को भेज देता है। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने एक अधिसूचना में कहा कि कास्टिक सोड़ा के चीन और कोरिया से आयात पर डंपिंग रोधी शुल्क को 17 नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। कास्टिक सोड़ा पर पहली बार डंपिंग रोधी शुल्क 18 अगस्त 2015 को पांच साल के लिए लगाया गया था। कास्टिक सोड़ा का उपयोग मुख्य तौर पर साबुन और डिटर्जेंट बनाने में होता है।

अब अपनों को शगुन में दीजिए बीमा का उपहार, इस कंपनी ने लॉन्च की पॉलिसी

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

एसबीआई जनरल इंश्योरेंस (SBI General Insurance) ने अपनी तरह की पहली पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी शगुन- गिफ्ट एन इंश्योरेंस लॉन्च करने की घोषणा की। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसके किसी को भी गिफ्ट किया जा सकता है। यानी इसे लेने वाले व्यक्ति का इंश्योर्ड का रिश्तेदार होना जरूरी नहीं है। शगुन पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस को कवर करती है जो बीमित व्यक्ति को दुर्घटना में मौत और आंशिक या पूर्ण विकलांगता की स्थिति में पूरी वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है।

इस मौके पर एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ पी सी कांडपाल ने कहा कि शगुन एसबीआई जनरल की एक अलग तरह की पॉलिसी है। भारतीय संस्कृति में हम अपनी उपलब्धियों या शुभ मुहूर्त पर एकदूसरे को गिफ्ट देते हैं या लिफाफा पकड़ाते हैं। ऐसा करना शुभ माना जाता है। इसी को ध्यान में रखकर शगुन की परिकल्पना की गई है। यही वजह है कि इस पॉलिसी का प्रीमियम 501, 1001 और 2001 रुपये रखा गया है। इसलिए इस पॉलिसी का नाम ही नहीं बल्कि प्रीमियम भी भारतीय परंपराओं के मुताबिक रखा गया है।

किसी को भी कर सकते हैं गिफ्ट

उन्होंने कहा कि शगुन को आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। इसे आप अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों, दूर के रिश्तेदारों और यहां तक कि घर में काम करने वाले लोगों को भी गिफ्ट कर सकते हैं। आप किसी भी मौके पर इसे गिफ्ट कर सकते हैं। किसी के परीक्षा पास करने, नई कार खरीदने, नया घर लेने, जन्मदिन, शादी, सालगिरह, नई बाइक खरीदने या कॉलेज में एडमिशन पर इसे गिफ्ट किया जा सकता है।

डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी भागीदारों को आठ साल तक संभाल कर रखने होंगे दस्तावेज

नयी दिल्ली। एजेंसी

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मंगलवार को कहा कि डिपॉजिटरीज और डिपॉजिटरी भागीदारों को दस्तावेज और अन्य रिकॉर्ड को कम से कम आठ साल के लिए संभाल के रखना होगा। बाजार नियामक सेबी ने अपने अक्टूबर 2019 में जारी आदेश में संशोधन जारी किया है। अक्टूबर के आदेश में दस्तावेज और रिकॉर्ड को पांच साल तक संभाल कर रखने की जरूरत बतायी गयी थी। सेबी के नए परिपत्र के मुताबिक, ''डिपॉजिटरीज और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को कम से कम आठ साल तक दस्तावेज एवं अन्य रिकॉर्ड संभाल कर रखने होंगे।'' सेबी ने कहा कि मूल दस्तावेजों को या तो भौतिक रुप में डिजिटल रूप में आठ साल के लिए सहेज कर रखना होगा। किसी तरह की जांच के दौरान कोई भी प्रत्यावर्तन एजेंसी इनकी प्रतिलिपि ले सकती है।

शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाक़ी निशाँ होगा

मध्यप्रदेश शासन

रानी लक्ष्मीबाई | चन्द्रशेखर आज़ाद | वीर सुरेन्द्र साए | भीमा नायक | शंकर शाह | रघुनाथ शाह | बरकतउल्ला भोपाली | रानी अवंतीबाई | टंट्या भील | तात्या टोपे | राणा बख्तावर सिंह | सीताराम कँवर | रघुनाथ सिंह मण्डलोई

आपका साथ मध्यप्रदेश का विकास

संबल योजना

गरीबों को फिर मिला संबल। एक अप्रैल से 31 जुलाई 2020 तक योजना के विभिन्न घटकों में 25 हजार से अधिक हितग्राहियों को 268 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता स्वीकृत।

पथ व्यवसायी योजना

आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण पथ विक्रेताओं को कार्यशील पूंजी का ब्याज मुक्त ऋण।

श्रम सिद्धि अभियान

प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा रोज़गार अभियान। 61 लाख 34 हजार 426 श्रमिकों का नियोजन। 3536 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का भुगतान।

श्रमिक आयोग का गठन

श्रमिकों को बेहतर जीवन दिलाने के एकाग्र प्रयासों की दिशा में अहम कदम।

रोज़गार सेतु पोर्टल

रोज़गार के अवसरों का नया आसमान। 13 लाख 10 हजार से अधिक श्रमिक और 31 हजार से अधिक नियोक्ता पंजीकृत। 38,900 से अधिक लोगों को रोज़गार मिला।

श्रम कानूनों में संशोधन

क्रांतिकारी संशोधनों से श्रमिकों के हितों का संरक्षण एवं औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन।

पंच परमेश्वर योजना पुन: प्रारंभ

52 हजार से अधिक गांवों के विकास के लिये 14वें वित्त आयोग के 1555 करोड़ रुपये तथा 15वें वित्त आयोग के 996 करोड़ रुपये जारी।

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

स्वतंत्रता दिवस
की
हार्दिक बधाई
एवं शुभकामनाएँ

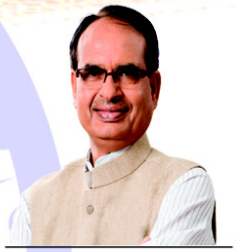

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री

आत्मनिर्भर व्यक्ति सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए
सभी व्यवस्थायें स्वयं कर लेता है।
आत्मनिर्भरता ही उन्नति का आधार है।
हम प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं।

शिवराज सिंह चौहान

गेहूँ उपार्जन में सबसे आगे

एक करोड़ 29 लाख 42 हजार मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन। देश में प्रथम स्थान।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

16 लाख किसानों को 3100 करोड़ रुपये की फसल बीमा राशि का एक क्लिक में भुगतान।

मंडी अधिनियम में सुधार

किसानों को घर बैठे देश की किसी भी मंडी में फसल बेचने की सुविधा। किसान एवं व्यापारी दोनों के लाभ की पहल।

चंबल प्रोग्रेस-वे

चंबल क्षेत्र को मिली विकास की अभूतपूर्व सौगात।

बिजली बिलों में राहत

97 लाख बिजली उपभोक्ताओं को 623 करोड़ रुपये से अधिक की राहत।

किल कोरोना अभियान

कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए 15 दिन का डोर-टू-डोर सर्वे अभियान।

उद्योगों को रियायतें

कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत उद्योग संवर्धन नीति एवं निवेश प्रोत्साहन योजना में लाभ ले रही औद्योगिक इकाइयों को संचालन तथा भुगतान संबंधी रियायतें।

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश से आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम

D-18014/2020

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

आकल्पन : म.प्र. माध्यम/2020

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल